

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
जनजाति कल्याण, उत्तरांचल,  
देहरादून।

संख्या : 1117/XVII(1)-01/2006-20(26)/2005

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 04 अक्टूबर 2006.

विषय : अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ संचालित स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता दिए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-22040/27/2003-एन.जी.ओ., दिनांक 02 जून 2005; समसंख्यक पत्र दिनांक 13 मार्च 2006 तथा दिनांक 29 मई 2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव पारित, पहचान, पुनर्निरीक्षण और अनुमोदन की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने का निर्णय लिया गया था।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों को समाविष्ट कर अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ संचालित स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता दिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश निर्गत किए जाते हैं—

(I) मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित परियोजना प्रस्तावों का वित्तीयन किया जाएगा—

- (i) स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।
- (ii) कम साक्षरता समूहों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना।
- (iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की योजना।
- (iv) आदिम जनजाति समूहों का विकास (स्वयंसेवी संघटक)।

(II) स्थापित स्वैच्छिक संस्थाओं (EVA) को प्रदत्त अनुदान अनेक कारकों पर निर्भर होगा, यथा—ऐसे अनुदान प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो सेवा-विहीन क्षेत्रों में अवस्थित हों, जनजाति क्षेत्रों आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों, एम.ए.डी.ए. क्लस्टर आदि में अवस्थित हों। इसके अतिरिक्त परियोजना सहायता स्वयंसेवी संस्था के कार्य निष्पादन, उसकी गतिविधियों की सेवाविहीन क्षेत्रों में आवश्यकता तथा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को आवंटित धनराशि पर भी निर्भर करेगी। यदि अन्य क्षेत्रों में स्थित प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाता है तो उसके लिए पर्याप्त व पूर्ण तर्क होने चाहिए। जहां तक सम्भव हो गैर जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं को उपयुक्त जनजातीय क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रयास किए जाएं।

- (XV) परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्ताव के साथ निरीक्षण रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाणपत्र, परीक्षित लेखा, लाभार्थियों की सूची, किराया मूल्यांकन प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) आदि राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
- (XVI) प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के लिए स्पष्ट संस्तुति अंकित की जाए।
- (XVII) यदि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने से छूट गया है तो वह केवल ऐसे ही प्रस्तावों को मंत्रालय के विचारार्थ संस्तुति सहित भेज सकती है।
- (XVIII) सर्वप्रथम पूर्व से जारी प्रस्तावों/वचनबद्ध गदों पर विचार किया जाएगा, तदोपरान्त ही नए परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- (XIX) ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव ही संस्तुत किए जाएं जो कि आवश्यक हैं तथा अल्पसेवा जनजाति क्षेत्र में संचालित हों।
- (XX) गैर जनजाति क्षेत्रों में जारी प्रस्तावों को अल्पसेवा जनजाति क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जाए। इसमें अधिसूचित क्षेत्र/MADA क्षेत्र/ITDP क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसे रोजगारपरक प्रशिक्षण केन्द्रों जो कि गैर जनजाति क्षेत्र में संचालित हैं उनको स्थानान्तरित करने से छूट प्रदान की जा सकती है या ऐसी परियोजनाओं को भी छूट दी जा सकती है जिनको स्थानान्तरित करने के पर्याप्त कारण हों। प्रत्येक प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि वह अल्प सेवा जनजाति क्षेत्र में अवस्थित है।
- (XXI) यदि स्वैच्छिक संस्था का कार्यालय गैर जनजाति क्षेत्र में है तो परियोजनाधिकारी के संज्ञान में विशेष रूप से यह तथ्य लाया जाए। संस्था का बैंक खाता वहां अवश्य होना चाहिए जहां परियोजना संचालित है।
- (XXII) सभी स्वैच्छिक संस्थाओं से यह शपथपत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वे रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) से अधिक की धनराशि का लेनदेन केवल बैंक द्वारा ही करेंगे। इसके अलावा मानवशक्ति से सम्बन्धित भुगतान भी चेक से ही किया जाए।
- (XXIII) ऐसे परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं जो कि कुछ समय के पश्चात् Phased Out हो जाएं। प्रस्ताव दशकों तक जारी रहने वाले न हों।
- (XXIV) परियोजना प्रस्ताव केवल एक ही किस्त में प्रस्तुत किए जाएं। सामान्यतया कोई ऐरियर ग्राण्ट स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए ऐरियर ग्राण्ट स्वीकृत की जा सकती है।
- (XXV) परियोजना के क्रियान्वयन की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संस्था का वार्षिक निरीक्षण किया जाए। केवल स्थापित स्वैच्छिक संस्थाओं (EVA) का त्रिवर्षीय निरीक्षण किया जाए।



(III) सुदूर भौगोलिक क्षेत्र में अल्प सेवा जनजाति क्षेत्रों का चिन्हांकन कर परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं, ताकि मंत्रालय की अपेक्षानुसार इनकी सूची उपलब्ध कराई जा सके। अल्पसेवा जनजाति क्षेत्रों से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सुविधाओं से वंचित हों। कृपया उक्तानुसार चिन्हांकन सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(IV) ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए जो कि सेवाविहीन क्षेत्रों में अपनी परियोजनाएं संचालित करें। चिन्हित सेवाविहीन जनजाति क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जहां कि मानव विकास सूचकांक कम हो तथा आधारभूत सुविधाएं खराब हों।

(V) किसी भी स्वयंसेवी संस्था को सामान्यतया (EVA को छोड़कर) एक राज्य में एक से अधिक परियोजना प्रस्ताव संचालित करने की अनुमति न दी जाए।

(VI) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित मानदण्ड तथा जिलाधिकारी व क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों के निरीक्षण हेतु मानक प्रारूप में ही प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं।

(VII) राज्य सरकार प्रस्तावों को प्राप्त कर उनकी पुनर्समीक्षा कर "स्वैच्छिक संस्थाओं के सहायतार्थ राज्य स्तरीय समिति" के अनुमोदनोपरान्त राज्य को निर्धारित बजट आवंटन की सीमा के भीतर मंत्रालय को उपलब्ध कराएगी।

(VIII) सामान्य नियम के तौर पर, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले और उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले समस्त ऋण, यदि कोई हों, उनके द्वारा नियोजित सम्पूर्ण स्टाफ का वेतन और रुपये 10,000/- से अधिक का लेन-देन Account Payee चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो अनुदान अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(IX) मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यक्षेत्रों की वरीयता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है—

- (i) शिक्षा।
- (ii) स्वास्थ्य।
- (iii) रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- (iv) कृषि।
- (v) अन्य विविध योजनाएं।

शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर जनजाति बालिका शिक्षा को वरीयता दिए जाने वाले प्रस्ताव प्रेषित किए जाएं।

(X) जनजाति क्षेत्रों में विकास के प्रयासों में कोई दुहराव नहीं होनी चाहिए।

(XI) परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें अनुदान जारी रखा जाए।

(XII) प्रस्तावित परियोजना की लागत निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

(XIII) मंत्रालय द्वारा राज्य को आवंटित धनराशि में 20 प्रतिशत का विचलन अनुमत्त होगा।

(XIV) यदि सभी प्रस्ताव एक ही क्षेत्र से हों तो पूर्व से संचालित परियोजनाओं को नई परियोजनाओं की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

- (XV) परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्ताव के साथ निरीक्षण रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाणपत्र, परीक्षित लेखा, लाभार्थियों की सूची, किराया मूल्यांकन प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) आदि राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
- (XVI) प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के लिए स्पष्ट संस्तुति अंकित की जाए।
- (XVII) यदि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने से छूट गया है तो वह केवल ऐसे ही प्रस्तावों को मंत्रालय के विचारार्थ संस्तुति सहित भेज सकती है।
- (XVIII) सर्वप्रथम पूर्व से जारी प्रस्तावों/वचनबद्ध गदों पर विचार किया जाएगा, तदोपरान्त ही नए परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- (XIX) ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव ही संस्तुत किए जाएं जो कि आवश्यक हैं तथा अल्पसेवा जनजाति क्षेत्र में संचालित हों।
- (XX) गैर जनजाति क्षेत्रों में जारी प्रस्तावों को अल्पसेवा जनजाति क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जाए। इसमें अधिसूचित क्षेत्र/MAIDA क्षेत्र/ITDP क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसे रोजगारपरक प्रशिक्षण केंद्रों जो कि गैर जनजाति क्षेत्र में संचालित हैं उनको स्थानान्तरित करने से छूट प्रदान की जा सकती है या ऐसी परियोजनाओं को भी छूट दी जा सकती है जिनको स्थानान्तरित करने के पर्याप्त कारण हों। प्रत्येक प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि वह अल्प सेवा जनजाति क्षेत्र में अवस्थित है।
- (XXI) यदि स्वैच्छिक संस्था का कार्यालय गैर जनजाति क्षेत्र में है तो परियोजनाधिकारी के संज्ञान में विशेष रूप से यह तथ्य लाया जाए। संस्था का बैंक खाता वहां अवश्य होना चाहिए जहां परियोजना संचालित है।
- (XXII) सभी स्वैच्छिक संस्थाओं से यह शपथपत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वे रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) से अधिक की धनराशि का लेनदेन केवल बैंक द्वारा ही करेंगे। इसके अलावा मानवशक्ति से सम्बन्धित भुगतान भी चेक से ही किया जाए।
- (XXIII) ऐसे परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं जो कि कुछ समय के पश्चात् Phased Out हो जाएं। प्रस्ताव दशकों तक जारी रहने वाले न हों।
- (XXIV) परियोजना प्रस्ताव केवल एक ही किस्त में प्रस्तुत किए जाएं। सामान्यतया: कोई ऐरियर ग्रांट स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए ऐरियर ग्रांट स्वीकृत की जा सकती है।
- (XXV) परियोजना के क्रियान्वयन की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संस्था का वार्षिक निरीक्षण किया जाए। केवल स्थापित स्वैच्छिक संस्थाओं (EVA) का त्रिवर्षीय निरीक्षण किया जाए।